



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236 ]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2003/भाद्र 31, 1925

No. 236 ]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2003/BHADRA 31, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2003

विषय : भारत में जापान, यूरोपीय संघ, नाईजीरिया और थाइलैण्ड से 6-हेक्सानेलेक्ट्रम के आयात के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 14/15/2003-डीजीएडी.—मै० टीपीएम कन्सलटेन्ट्स प्रा० लि० ने मै० गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० और मै० फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स श्रावणकोर लि० की ओर से सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पैहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें जापान, यूरोपीय संघ, नाईजीरिया और थाइलैण्ड मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित 6-हेक्सानेलेक्ट्रम के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

### विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद जापान, यूरोपीय संघ, नाईजीरिया और थाइलैण्ड के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित 6-हेक्सानेलेक्ट्रम है। 6-हेक्सानेलेक्ट्रम एक मोनोमर है और नाइलोन-6 के उत्पादन के लिए आधारभूत सामग्री है। 6-हेक्सानेलेक्ट्रम को तरल तथा ठोस दोनों रूपों में बनाया और बेचा जाता है। 6-हेक्सानेलेक्ट्रम के तरल रूप को केवल उन ग्राहकों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है जो उक्त सामग्री के स्रोत के काफी समीप होते हैं। भारत के उत्पादक इस सामग्री के केवल ठोस रूप का उपयोग करते हैं।

इस सामग्री का ठोस रूप सफेद क्रिस्टल या फ्लेक्स रूप में होता है ! इन तरल और ठोस रूपों में भौतिक स्वरूप में अन्तर के अलावा और कोई अन्तर नहीं होता है । इसके अलावा दोनों प्रकार के ठोस रूप भी एक दूसरे से केवल भौतिक दृष्टि से भिन्न होते हैं । इसे वाणिज्यिक रूप से कैप्रोलेक्टम के नाम से भी जाना जाता है ।

6-हेक्सानेलेक्टम प्राथमिक रूप से नाइलोन-6 के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है जिससे इसके बाद नाइलोन यार्न का उत्पादन होता है । नाइलोन यार्न का उपयोग (क) वस्त्रों और (ख) दायर कोर्ड फैब्रिक में उपयोग के लिए नाइलोन फैब्रिक के उत्पादन में होता है ।

6-हेक्सानेलेक्टम को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय-29 के तहत वर्गीकृत किया जाता है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार इस उत्पाद का सम्पूर्ण विवरण 29337100 6-हेक्सानेलेक्टम (एपसी लोन -कैप्रोलैक्टम) है ।

#### 2. घरेलू उद्योग की स्थिति

वर्तमान याचिका मै0 गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि�0, बडोदरा और मै0 फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि�0, तिरुवनंतपुरम (भारत सरकार का एक उद्यम) द्वारा संयुक्त रूप से दायर की जा रुही है ।

#### 3. शामिल देश/क्षेत्र

वर्तमान जांच में शामिल देश/क्षेत्र जापान, यूरोपीय संघ, नाईजीरिया और थाइलैण्ड हैं (जिन्हें आगे संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है)

#### 4. समान वस्तुएं

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु जापान, यूरोपीय संघ, नाईजीरिया और थाइलैण्ड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तुएं हैं । याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश/क्षेत्र से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

### 5. पाटन और पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य:- याचिकाकर्ता ने निर्यातक देशों के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमत के आधार पर जापान, यूरोपीय संघ, नाईजीरिया और थाइलैण्ड के मामले में सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

निर्यात कीमतः- याचिकाकर्ता ने आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है।

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि जापान, यूरोपीय संघ, नाईजीरिया और थाइलैण्ड में विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस कीमत से काफी अधिक है जिस कीमत पर इसका भारत को निर्यात किया गया है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह पता चलता है कि जापान, यूरोपीय संघ, नाईजीरिया और थाइलैण्ड के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

6. क्षति एवं कारणात्मक संबंधः- घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक मापदंड जैसे कि उत्पादन, बिक्री, लाभ/हानि इत्यादि सामूहिक एवं संचयी रूप से यह संकेत देते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

### 7. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

**8. जांच की अवधि**

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2002 से 30 जून, 2003 (15 महीने) तक की है।

**9. सूचना प्रस्तुत करना**

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत के आयातकों जो इस जांच के संबंध में ज्ञात हैं, को निर्धारित विधि और पद्धति से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है और उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि वे अपने विचारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय, पाटनरोधी निदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को अवगत कराएं। अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार जांच से संबंधित अपने निवेदन निम्नानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित विधि ओर पद्धति में कर सकता है।

**10. समय सीमा**

वर्तमान जांच से संबंधित काई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।

**11.** चूँकि, पाटनरोधी जांच एक समयबद्ध कार्यवाही है, तथापि निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार दी गई सीमा के भीतर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा किसी भी तरह से सूचना के अपूर्ण होने की स्थिति में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

**12. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

13. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करती है अथवा महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है अथवा सूचना किसी भी रूप में अधूरी होती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2003.

**Subject :** Initiation of anti-dumping investigations concerning import of 6-Hexanelactam from Japan, European Union, Nigeria and Thailand in India.

No. 14/15/2003-DGAD.— M/s TPM Consultants Pvt. Ltd., New Delhi, on behalf of M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd., and M/s. Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of 6-Hexanelactam originating in or exported from Japan, European Union, Nigeria and Thailand and has requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

**1. Product Under Consideration:**

Product under consideration is 6-Hexanelactam, originating in or exported from Japan, European Union, Nigeria and Thailand. 6-Hexanelactam is a monomer and is a base material for production of Nylon-6. 6-Hexanelactam is produced and sold in both liquid and solid forms. Liquid form of the material can be used only by those customers who are very close to the source of the material. Producers in India use only solid form of the material. Solid form of the material is in white crystal or flakes form. There is no difference in the liquid or solid form, except for the difference in the physical forms. Further, the two solid forms also differ with each other only in terms of physical forms. It is commercially also known as Caprolactam.

6-Hexanelactam is primarily used in production of Nylon-6, which in turn is used for production of Nylon Yarn. Nylon Yarn is used for production of Nylon Fabric for use in (a) apparels; and (b) tyre cord fabric.

6-Hexanelactam is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. Complete description of the product as per Customs Tariff Act is 29337100 6-Hexanelactam (epsilon-Caprolactam).

**2. Domestic Industry Standing:**

The Present petition is being jointly filed by M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd., Vadodara and M/s. Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Thiruvananthapuram (A Government of India Enterprises).

**3. Country(ies)/ Territory Involved:** The countries/territory involved in the present investigations are Japan, European Union, Nigeria and Thailand (referred to as subject countries/territory hereinafter).

**4. Like Goods:** The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from Japan, European Union, Nigeria and Thailand. Goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject countries/territory within the meaning of the Rules.

**5. Dumping and Dumping Margin :**

**Normal Value:** The petitioner has constructed the normal value in case of Japan, European Union, Nigeria and Thailand on the basis of price prevailing in the domestic market of the exporting countries.

**Export price:** The petitioner has claimed export price based on the import figures.

Considering the normal value and export price the dumping margins are significantly higher than the de-minimis limit.

There is sufficient evidence that the normal values of the product under consideration in the Japan, European Union, Nigeria and Thailand are significantly higher than the prices at which it has been exported to India, indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped by the exporters from Japan, European Union, Nigeria and Thailand.

**6. Injury and Causal Link:** The various economic indicators relating to domestic industry such as, production, sales, profit/loss etc. collectively and cumulatively, indicates that the domestic industry has suffered injury. There is sufficient *prima facie* evidence that the imports of the product under consideration have caused material injury to the domestic industry.

**7. Initiation of Anti-Dumping Investigation:** In view of the foregoing paragraph, the Designated Authority initiates anti-dumping investigations to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries/territory.

**8. Period of Investigation:** The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1<sup>st</sup> April, 2002 to 30<sup>th</sup> June, 2003 (15 months).

**9. Submission of Information:** The exporters in the subject countries/territory and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Directorate of Anti- Dumping, Udyog Bhavan, New-Delhi –110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

**10. Time Limit:** Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.

**11. Anti-dumping investigations being a time bound exercise, the Designated Authority may record its findings on the basis of facts available on record in accordance with the Rules supra, if no response is received within the time stipulated or the information is incomplete in any respect.**

**12. Inspection of Public File:** In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**13. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.**

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority